Imoprt of Fertilizer

1225. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to import fertiliser on a large scale during the year 1984-85;

(b) if so, what is the quantity of fertiliser proposed to be imported during the current financial year;

(c) what is the main purpose of importing fertiliser; and

(d) what will be the cost of the fertiliser proposed to be imported?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (d) Since the indigenous production of fertilisers is less than the consumption, fertilisers are being imported in adequate quantities so as to meet the requirements of the States. It would not be in the public interest to disclose the details with regard to the exact quantities, source of import and price of import for these fertilisers.

रामेश्वरम् को मंडपम से जोड़ने वाले सड़क पुल का निर्माण

1226. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में रामेश्वरम् को मंडपम् से जोड़ने वाले सड़क पुल का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ख) पुल की लम्बाई कितनी है और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और

(ग) पुल के कब तक यातायात के लिए खोल दिए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी): (क) इस पुल के निर्माण के लिए 532.37 लाख रु० की अनुमानित राशि को मार्च, 1972 में मंजूरी दी गई थी और इसका निर्माण कार्य अक्तूबर, 1974 में शुरू कर दिया गया था। तथापि 1978 में पुल के स्थान पर तूफान आने से ठेकेदार के आधारभूत उपकरणों को काफी क्षति पहुंची जिसके कारण जुलाई, 1979 में इस पुल का निर्माण कार्य ठप्प पड़ गया। राज्य सरकार ने 1978 में यह ठेका रद्द कर दिया और नए टेंडर आमंत्रित किए गए। शेष निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए जनवरी, 1984 में ठेका दे दिया गया और इस पुल के निर्माण कार्य की मौजूदा सकल प्रगति 38% है।

(ख) और (ग) इस पुल की कुल लंबाई 2350 मीटर है और इस पुल को मार्च, 1987 मे तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

स्कूली शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा के संबंध में दो राष्ट्रीय आयोगों का प्रतिवेदन

1227. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या स्कूली शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा के संबंध में फरवरी, 1983 मे नियुक्त दो राष्ट्रीय आयोगों की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दोनों आयोगों की अन्तरिम रिपोर्टें 25 जून, 1984 को सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं। आशा है कि अन्तिम रिपोर्ट सितम्बर, 1984 के अन्त तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि

1228. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में अंतिम बार वृद्धि 1973 में की गई थी और तब से अब तक उनके वेतनमानों में कोई वृद्धि नहीं की गई है ; और

(ख) क्या सरकार वेतनमानों में संशोधन करने का विचार रखती है और यदि हां, तो नए वेतनमान कब तक लागू कर दिए जायेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के वेतनमान पिछली बार 1-1-1973 से संशोधित किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में और संशोधन करने पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति का कार्य प्रगति पर है।

Suggestion of FICCI regarding industrial licensing

1229. SHRI NAND KISHORE BHATT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has suggested that approval of industrial licensing and clearance under the Monopolies Restrictive Trade Practices Act should be vested in a single authority to minimise the delays and help Government to take an integrated view of development;

(b) if so, what are the details thereof. and

(c) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI PATTABHI RAMA RAO): (a) and (b) In a Resolution on Cost of Controls and Regulations adopted at its 57th Annual General Meeting, the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has suggested certain measures to streamline the licensing procedures with a view to minimise the delays in giving approvals. One of the suggestions made by the Federation is that sanction of industrial licences and clearances under the MRTP Act should be vested in a single authority.

(c) With a view to minimise delays in giving industrial approvals, Government have taken various measures to streamline the licensing procedures. Single point clearances in respect of various proposals concerning the licensing, import of capital goods, and foreign collaboration are being provided by the Projects Approval Board, Board for 100 per cent Export Oriented Units and Special Approval Committee for the Non-resident Indians. Government is constantly endeavouring to encourage single window clearances wherever possible and to minimise the delays in providing clearances.

Construction of Houses for Weaker Sections

1230. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the number of houses which are to be constructed for the weaker